(3) To consider demands for different varieties of potato in the different varieties of potato in the and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demand through suitable development programmes,

(4) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of potato production and suggest suitable measures for meeting the same;

(5) To facilitate coordination between research and development programmes relating to potato and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of potato.

(6) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

In addition, the Indian Potato Development Council is also empowered to set up Standing Committee, Technical Committee and Ad-hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necesarry for specific purposes.

Memorandum from All India Postal Employees Union Class III

*946. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the All India Postal Employees Union Class III has recently submitted any memorandum to his Department about their problems; and

(b) if so, the decision taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) In the absence of particulars such as reference, date, subject etc., it has not been possible to identify the specific memorandum which the Hon'ble Member has in her mind.

(b) Does not arise.

Foodgrains to Orissa under Rural Development Works

*947 SHRI SARAT KAR: Will the the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether any requests have been made by the Government of Orissa to the Central Government for the supply of foodgrains to that State for the rural development works during the next financial year, and

(b) if so, the reaction of Central Government thereon?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes Sir. The Government of Orissa have requested for the supply of a total quantity of 3 lakhs tonnes of foodgrains under 'Food for Work Programme' during the year 1979-80.

(b) Keeping in view the demands of the State Governments and the total quantity of foodgrains likely to be made available for the purpose, it may not be possible to supply this much quantity to Orissa, this year.

चिलगोजे का उत्पादन

*948. श्री गंगा सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे गत तीन वर्षों मे, चिलगोजे का उत्पादन (वर्षवार) कितना हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसका उत्पादन बढ़ाने का है और यदि हा, तो इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या चिलगोजा के बारे में कोई अनुसधान करने के लिये भारत सरकार ने प्रयास किये हैं, और यदि हा, तो उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) चिलगोजे के वृक्ष केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में ही पाये जाते हैं। इन राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार चिलगोजे के उत्पादन के बारे में कोई प्रामाणिक आकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष 300—400 मीटरी टन चिलगोजे का उत्पादन के अलावा जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में व्यापारिक पैमाने पर चिलगोजे का विशेष उत्पादन नहीं है।

(ख) जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा बताया गया है, चिलगोजे के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अभी तक कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ नहीं किये गये हैं।

(ग) चिलगोजे पर अभी तक वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कोई अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में बागवानी निदेशक तथा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक आधार पर कुछ कार्य प्रारम्भ किया गया है। तथापि, वन अनुसंधान संस्थान द्वारा ऊंचे स्थानों के शुष्क क्षेत्रों पर क्रियान्वित की जा रही अनुसंधान योजनाओं के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि चिलगोजे पर अनुसंधान के कार्य को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

जिला मन्दसौर में मन्दिरों का रखरखाव

9091. **श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री होशंगाबाद जिले में कार्य के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 101, दिनांक 20 नवम्बर, 1978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने उच्चतर अधिकारी के जिला मन्दसौर में गुप्त काल के मंदिरों के रख-रखाव हेतु 1975 से 1978 के बीच किये गये कार्यों का स्थल पर जा कर निरीक्षण किया था और यदि हां, तो क्या कार्य के नियमों के अनुसार सन्तोषजनक पाया गया था, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन कार्यों के संबंध में समुचित ढंग से कोई जांच की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां। मन्दसौर जिले में स्थित गुप्तकालीन मन्दिर का निरीक्षण अप्रैल, 1977 में उप अधीक्षण पुरातत्वविद् द्वारा किया गया था। वर्ष 1976—77 के दौरान कोई मरम्मत-कार्य नहीं किया गया। वर्ष 1977—78 के दौरान किए गए कार्यों की जांच सहायक अधीक्षण पुरातत्व-अभियन्ता ने की थी और वे कार्य सन्तोषजनक पाए गए।

Outlay for Dairy Development during VI Plan

9002. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the proposed outlay for Dairy Development for the next Plan period;

(b) details of generating financial resources for the scheme;

(c) whether the proposal for generating resources through the sale of commodities donated by EEC is under the consideration of Government; and

(d) if so, expected resources thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d) The proposed outlay for Operation Flood II, an integrated Dairy Development Project, is estimated to be Rs. 485.50 crores for the period 1978—85, of which the outlay during the Sixth Plan will be Rs. 386 crores. The resources are indicated below:

(i) IDA loan Rs. 129 crores

(ii) Generation of funds by sale of EEC commodities . Rs. 206 crores

(iii) Internal resources of IDC . Rs. 75 crores

(iv) Balance of Rs. 75·5 crores through budgetary support or further IDA credit or both.